Eastern Railway
(Personnel Department)
17, N. S. Road, Kolkata -700 001

CPO's S.L. No.117/2020

NO: E.890/0/1/R&R/Policy/Pt. XIX Kol. dt. 07.12.2020

All Concerned,
(as per standard list)

Sub: Filling up of posts in ongoing electrification projects undertaken by CORE.

***

A photocopy of Railway Board's letter No.E (NG)I-2014/TR/17 dated 08.09.2020 (**RBE No.79/2020**) on the above mentioned subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action. Board's earlier letter No.E (NG) I-2014/TR/17 dated 05.10.2017 (RBE No.143/2017) was circulated vide **PCPO's Sl.No.143/2020.**

DA: As above

(S. Bhattacharya)
Sr. Personnel Officer (S&T)
for Chief Personnel Officer

Index No. 1063: Filling up of posts in ongoing electrification projects undertaken by CORE.

RBE No.79/2020

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2014/TR/17 **New Delhi dated 08.09.2020**

The General Managers (P)
All Indian Railways, Production Units.
(As per standard list).

Sub: Filling up of posts in ongoing electrification projects undertaken by CORE.

*****

Attention is invited to Board's letter of even number dated 05.10.2017, wherein it was clearly stated that filling up of vacancies of CORE projects shall primarily be the responsibility of the Zonal Railway in whose territorial jurisdiction the electrification project is being undertaken. The concerned General Managers and Divisional Railway Managers should tie up with the concerned Heads of the RE project to ensure posting of sufficient number of staff in a manner similar to that for construction projects. It was also stipulated therein that the Zonal Railway concerned need not ask for option or willingness from any staff and arrange to post the technical/non-technical staff working at any level after assessing suitability and requirement of the project.

2. The General Manager/CORE, in the MCDO upto June, 2020, has pointed out that there is an acute shortage of supervisors in the projects; which is adversely affecting the progress of electrification works. He has requested that Zonal Railways may be impressed upon to spare the Non-Gazetted Supervisors.

3. The matter has accordingly been considered. It is observed that the difficulty of shortage of staff being faced by CORE may cause delay in the execution of the projects handled by them, impacting the unit cost of operations in Indian Railways adversely.

4. The instructions contained in Board's letter dated 05.10.2017 ibid are accordingly reiterated for strict compliance. Necessary action may be taken to spare the Non-Gazetted Supervisors for the R.E. Projects at the earliest.

Please acknowledge receipt.

(M. K. Meena)
Deputy Director Estt. (N)
Railway Board

Copy to: -
The General Manager
Central Organization for Railway Electrification,
Allahabad.

Contd.....2/-

आरबीई सं.79/2020

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)I/2014/टीआर/17 **नई दिल्ली, दिनांक 08.09.2020**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन द्वारा शुरू की गई मौजूदा विद्युतीकरण परियोजनाओं में पदों को भरना।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 05.10.2017 के समसंख्यक पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की परियोजनाओं की रिक्तियों को भरने की मुख्य जिम्मेदारी उस क्षेत्रीय रेलवे की होगी, जिसके क्षेत्राधिकार में विद्युतीकरण परियोजना का कार्य किया जा रहा है। संबंधित महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक रेल विद्युतीकरण परियोजना के प्रमुख के साथ मिलकर निर्माण परियोजनाओं की भांति पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करें। यह भी निर्धारित किया गया था कि संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को किसी भी कर्मचारी से विकल्प या उसकी सम्मति मांगने की आवश्यकता नहीं है और परियोजना की उपयुक्तता और आवश्यकता का आकलन करने के बाद किसी भी स्तर पर कार्यरत तकनीकी/गैर-तकनीकी कर्मचारी को तैनात करने की व्यवस्था करें।

2. महाप्रबंधक/केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन के जून तक के एमसीडीओ में उल्लेख किया गया है कि परियोजनाओं में पर्यवेक्षकों की भारी कमी है, जिससे विद्युतीकरण के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि क्षेत्रीय रेलों को अराजपत्रित पर्यवेक्षकों को कार्यमुक्त करने के संबंध में समझाया जाए।

3. तदनुसार मामले पर विचार किया गया है। यह देखा गया है कि केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन द्वारा कर्मचारियों की कमी का सामना करने के कारण उनकी परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हो सकता है, जिससे भारतीय रेल में परिचालनिक इकाई लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

4. तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 05.10.2017 के उक्त पत्र में निहित अनुदेशों के कड़ाई से पालन को दोहराया जाता है। रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए अराजपत्रित पर्यवेक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

कृपया पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

Central Registry, ... Rly
Date of Receipt
Serial No. ...22 2/12
03 DEC 2020
PCPO
PCPO E-OFFICE